

प्रेषक,

राधा रतूडी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड ।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 23 सितम्बर, 2015

विषय: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत हकदार परिवारों के अतिरिक्त राज्य की अवशेष आबादी को उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना से आच्छादित कर खाद्यान्न आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राज्य की 61.94 लाख जनसंख्या हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर खाद्यान्न का आवंटन निर्गत किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त जनसंख्या के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य की अवशेष आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना को दिनांक 01.10.2015 से लागू करते हुये इस योजना से आच्छादित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त निर्णय के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत राज्य की अवशेष आबादी (लगभग 66 लाख) में से ऐसे परिवारों, जिनकी आय ₹ 5.00 लाख वार्षिक या उससे अधिक हो अथवा आयकर दाता हों, को इस योजना से पृथक कर राज्य खाद्य योजना के राशनकार्ड निर्गत करते हुये 15.00 कि०ग्रा० खाद्यान्न प्रतिकार्ड/प्रतिमाह (10 कि०ग्रा० चावल ₹ 9.00 प्रति कि०ग्रा० एवं 5 कि०ग्रा० गेहूँ ₹ 5.00 प्रतिकि०ग्रा० की दर से) उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

3. भारत सरकार से Tide Over Allocation के अन्तर्गत केन्द्रीय निगमन दरों पर आवंटित खाद्यान्न (5669.40 मी०टन गेहूँ एवं 2792.40 मी०टन चावल प्रतिमाह) में प्रतिमाह कम पड रही 10418 मी०टन चावल की मात्रा का क्रय राज्य में कार्यरत चावल मिलर्स से किया जायेगा।

क्रमशः.....2 पर

4. उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना के अर्न्तगत तत्काल राशनकार्डों का डिजिटाइजेशन एक अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए।
5. उच्च वर्ग की आबादी को उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना से पृथक करने हेतु अन्य सम्बन्धित विभागों जैसे आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, वाणिज्यिक कर, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादी में उपलब्ध डाटा बेस का भी प्रयोग किया जाए, ताकि आय का क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके।

भवदीया,
(राधा रतूड़ी),
प्रमुख सचिव।

संख्या-420(i)/15-XIX-2/89 खाद्य/2013 टी0सी01 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, सहारानपुर रोड, माजरा, देहरादून।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 4- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 8- वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूँ/गढ़वाल सम्भाग, हल्द्वानी/देहरादून।
- 10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 11- वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
- 12- मुख्य विपणन अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
- 13- उपायुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
- 14- समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 15- सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी(खाद्य), गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग, देहरादून/हल्द्वानी।
- 16- उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/पौड़ी/हल्द्वानी/उधमसिंह नगर।
- 17- समन्वयक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन।
- 18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राधा रतूड़ी),
प्रमुख सचिव।